This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 13 सितम्बर, 2017 / 22 भाद्रपद, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 12th September, 2017

No.1-73/70-Fin (LA) Part-5599.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Padam Singh Kanwar, Joint Director (Class-I-Gazetted) Local Audit Department, H.P. to the post of Additional Director (Class-I-Gazetted) in the pay band of ₹ 15600-39100+8400 Grade Pay with immediate effect.

Consequent upon the above promotion, Shri Padam Singh Kanwar will remain posted in the Headquarter Office, Local Audit Department, Shimla-171009 against vacant post.

He will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Finance).

————————

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 08 सितम्बर, 2017

संख्याः रैव डी (जी) 6–69/2011–III.––हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2017 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29–06–2017 द्वारा, हिमाचल प्रदेश–भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जन साधारण से आक्षेपों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए 01–07–2017 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश–भू–जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 (1973 का अधिनियम संख्यांक 19) की धारा 26 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः रैव डी (जी) 6–69/2011–II तारीख 4–03–2014 द्वारा अधिसूचित और तारीख 05–03–2014 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम, कहा गया है) के नियम 4 के उप नियम (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''(*vii*) राजनैतिक पार्टियों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समुदायों के कल्याण बोर्ड़ों और कर्मचारी संघों/सगठनों को उनके सामाजिक दायित्वों और अन्य क्रियाकलापों के निर्वहन के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण।''।

3. **नियम 5 का संशोधन.**––उक्त नियमों के नियम 5 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु भारत के निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टियों तथा अन्य संगठनों की बाबत सरकारी भूमि को, परियोजना रिपोर्ट, भवन प्लान और नक्शे के आधार पर अपेक्षा के अनुसार और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, अधिकतम एक बीघा तक पट्टे के आधार पर, मंजूर किया

जा सकेगा। ऐसी राजनैतिक पार्टियों को भूमि को पट्टे के आधार पर परिशिष्ट–'क' में यथानियत विहित शर्तों और अपेक्षाओं को पूरा करने पर आबंटित किया जा सकेगा। ''।

4. नियम 8 का संशोधन.––उक्त नियमों के नियम 8 में, खण्ड (iii) में विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

''परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में पट्टा भाटक/रकम को, इस नियम के खण्ड (*i*) के उपबंध के अनुसार या इस नियम के खण्ड (*iii*) के उप खण्ड (घ) के परन्तुक में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार, जो राज्य सरकार उचित समझे, प्रभारित किया जाएगा । ''।

आदेश द्वारा,
तरूण श्रीधर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

––––––––––

परिशिष्ट–'क'

हिमाचल प्रदेश में राजनैतिक पार्टियों को पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि के आबंटन हेतु शर्तें और अपेक्षाएं

1. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक पार्टियों जिनके पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि के आबंटन के लिए आवेदन करते समय राज्य विधान सभा में विधान सभा सदस्यों की कम से कम एक चौथाई संख्या अर्थात्, सत्रह विधान सभा सदस्य है। राजनैतिक पार्टियां तीन पूर्ववर्ती निर्वाचनों के दौरान राज्य विधान सभा की निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भाग ले रही हो, तभी वह पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि के आबटंन के लिए हकदार होगी।

2. राजनैतिक पार्टियों को, भारत के निर्वाचन आयोग से प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टी के रूप में उनकी प्रास्थिति और मान्यता की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

3. किसी राजनैतिक पार्टी को सरकारी भूमि को भूमि की उपलब्धता पर जिला मुख्यालय में उपलब्ध करवाया/आबंटित किया जाएगा और उस पर विनिर्मित कार्यालय भवन का उपयोग राजनैतिक पार्टियों द्वारा अपने राज्य/जिला/मण्डल स्तरीय इकाई कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के लिए ही किया जाएगा। इन परिसरों का उपयोग केवल कार्यालय प्रयोजन तथा आनुषंगिक क्रियाकलापों, जो कार्यालय के कार्यकरण में सहयोगी हो, के लिए किया जाएगा।

4. जब कोई राजनैतिक पार्टी अस्तित्व में नहीं रहती है तो आबंटित भूमि का कब्जा उस पर विनिर्मित अवसंरचना सहित तथा समस्त विल्लगमों से रहित सरकार द्वारा ले लिया जाएगा। यथापि, जब किसी राजनैतिक पार्टी का विभाजन हो जाता है तो पट्टे पर दी गई भूमि और अवसरंचना राजनैतिक पार्टी के उस भाग के साथ रहेगी, जो न्यायालय/निर्वाचन आयोग द्वारा आबटंन के समय मूल पार्टी की प्रास्थिति/प्रतीक प्रतिधारित करेगी।

5. आबंटिती पार्टी भवन का निर्माण केवल सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी से भवन–नक्शा अनुमोदित करवाने के पश्चात और अन्य कानूनी बाध्यताओं/प्रवृत्त नियमों/अधिनियमों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के पश्चात् ही करेगी।

6. सम्बद्ध राजनैतिक पार्टी को, इस प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्वाचन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से, आवेदित भूमि के सम्बन्ध में अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा।

7. आबटंन निम्नलिखित परिस्थितियों में विखंडित / रद्द किए जाने के लिए दायी होगाः——

(क) यदि आबंटिती / पट्टेदार नियत अवधि के भीतर आबटंन / पट्टा विलेख के निबंधनों के अनुसार पट्टा भाटक / धन या किसी अन्य सरकारी देय का संदाय करने में असफल रहता है।

(ख) यदि पार्टी, भूमि के आबटंन और स्थानीय निकाय द्वारा भवन योजना के लिए अनुमोदन के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के भीतर भवन विनिर्माण करने में असफल रहती है।

(ग) पट्टा विलेख या किसी कानूनी नियम / अधिनियम के किसी निबन्धन और शर्त के अतिक्रमण की दशा में।

——————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev-D (G) 6-69/2011-III, dated 08-09-2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 08th *September,* 2017

No.Rev-D(G)6-69/2011-III.—WHEREAS, the draft Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2017 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 1st July, 2017 for inviting the objections and suggestions from the General Public *vide* this Department Notification of even number dated 29-06-2017 as required under Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973);

AND WHEREAS, no objection or suggestion has been received in this behalf, within the stipulated period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974 (Act No. 18 of 1974) read with Section 26 of the Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act, 1972 (Act No. 19 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 notified *vide* this Department Notification No. Rev-D (G)6-69/2011 Part-III dated 04-03-2014 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 05-03-2014, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lease (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Rule 4.—In Rule 4 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 (hereinafter referred to as the 'said rule') after sub- rule (vi), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(vii) Political Parties, Social Organizations, Welfare Boards of different communities and Employees Associations / Organisations for the construction of Office Building to meet out their social obligations and other activities. "

3. Amendment of Rule 5.— In rule 5 of the said rules, at the end, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the Government land in respect of the National Political Parties recognised by the Election Commission of India and other organizations may be sanctioned on lease basis upto the maximum limit of 1-00 Bigha only on the basis of Project Report , Building Plan and map as per requirement and on actual need basis. The land may be allotted to such Political Parties on lease basis on fulfilment of prescribed conditions and requirements as stipulated in Appendix-A".

4. Amendment of Rule 8.—In rule 8 of the said rules, in clause (iii), after the existing proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the lease rent / amount in such cases shall be charged as per provision of clause (i) of this rule or as specified in proviso to sub-clause (d) of clause (iii) of this rule as the State Government may deem fit."

By order,
TARUN SHRIDHAR,
Addl. Chief Secretary (Revenue).

APPENDIX-A

CONDITIONS AND REQUIREMENTS FOR ALLOTMENT OF THE GOVERNMENT LAND ON LEASE BASIS TO THE POLITICAL PARTIES IN HIMACHAL PRADESH

(1) The National Political Parties recognized by the Election Commission of India and having at least 1/4th strength of MLAs in State Assembly, *i.e.*, 17 MLAs at the time of applying for allotment of Government land on lease basis. The Party should have been actively taking part in the election process of State Legislative Assembly during the previous 3 elections, will be entitled for allotment of land for construction of party Office Building / Bhawan.

(2) Political Parties should furnish a certificate from the Election Commission of India confirming their status and recognition as a National /State recognized political party.

(3) The government land will be provided / allotted to any political party at District Headquarter on availability of land and the office building constructed thereon shall be utilized by the political parties for their State /District/Block level units programmes / activities only. These premises shall be utilized only for office purpose and the ancillary activities which support the functioning of the office.

(4) When a political party cease to exist, the allotted land alongwith infrastructure created thereon shall be resumed by the Government free from all encumbrances. However, when a political party get divided / splitted, the leased land and infrastructure shall remain with the fraction of the political party, who will retain the status / symbol of the original party at the time of allotment by the Court of Law/the Election Commission.

(5) The allottee party shall construct the building only after getting the building plans approved from the concerned local authority and other statutory obligations / requirements of Rules/ Acts in force are fulfilled.

(6) The concerned political party will require to obtain the Essentiality Certificate in respect of the applied land from the competent authority of Election Department of HP Government for this purpose.

(7) The allotment shall be liable to be rescinded/cancelled in the following circumstances:—

(*a*) If the allottee/ lessee fails to make the payment of lease rent/ money or any other Govt. dues in accordance with the terms of allotment/lease deed within the stipulated time.

(*b*) If the party fails to construct the building within a period of 2 years after the allotment of land and approval for building plans by the local body.

(*c*) In case of violation of any terms and condition of lease deed or any statutory Rules / Acts.

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्याः गृह(ए)बी(1)–29 / 2016.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, पुलिस चौकी माजरा का दर्जा बढ़ाकर पुलिस थाना, माजरा करते हैं, और निम्नलिखित अनूसूची की स्तम्भ संख्याः 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्याः 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्याः 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र को अन्तरित करते हैं, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम संखा	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना जिससे अन्तरित किए जाने हैं	पुलिस थाना जिसमें सम्मिलित किए जाने हैं
1	2	3	4	5
1.	ग्राम पंचायत, पुरूवाला	1. संतोषगढ़ 2. अमरगढ़ 3. पुरूवाला कांशीपुर 4. बल्लूवाला	पुलिस थाना पांवटा–साहिब	पुलिस थाना माजरा

2.	ग्राम पंचायत, पिपलीवाला	1. पिपली वाला 2. जोहड़ो 3. किरतपुर 4. भगवानपुर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
3.	ग्राम पंचायत, मिश्रवाला	1. मिश्रवाला 2. क्यारदा	–यथोपरि–	–यथोपरि–
4.	ग्राम पंचायत, पलहोडी	1. पलहोड़ी 2. सिम्बल बाड़ा	–यथोपरि–	–यथोपरि–
5.	ग्राम पंचायत, माज़रा	1. नया गांव माज़रा 2. फतेहपुर 3. जगतपुर 4. मेलीयों 5. चुरक माज़री 6. मटक माज़री	–यथोपरि–	–यथोपरि–
6.	ग्राम पंचायत, सैनवाला मुबारिकपुर	1. सैनवाला 2. टोकियों 3. बेहडेवाला 4. खैरी 5. घुंघलों	–यथोपरि–	–यथोपरि–
7.	ग्राम पंचायत, धौलाकुआं	1. धौलाकुआं 2. भारापुर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
8.	ग्राम पंचायत, कोलर	1. कोलर 2. सुखचैनपुर 3. फांदी बोडीवाला	–यथोपरि–	–यथोपरि–
9.	ग्राम पंचायत, हरिपुर खोल	1. कोदेवाला 2. चरणावाला 3. झीलबांका बाड़ा 4. लोहगढ़ 5. जामनीघाट 6. मेहता वाला	–यथोपरि–	–यथोपरि–
10.	ग्राम पंचायत, बाडथल मधाना	1. साहा 2. मधाना 3. जंगलोट 4. बाड़थल	–यथोपरि–	–यथोपरि–
11.	ग्राम पंचायत, रामपुर भारापुर	1. घुंघलो 2. रामपुर माज़री 3. रामपुर बंजारन	–यथोपरि–	–यथोपरि–
12.	ग्राम पंचायत, पड़दूनी	1. पड़दूनी 2. गिरी नगर 3. मेहराड	–यथोपरि–	–यथोपरि–

13.	ग्राम पंचायत, काण्डो कांसर	1. स्वाड़ा नडासी 2. मन्धारा 3. काण्डो फागड़ 4. कटवाड़ी बागड़त 5. तनलोग 6. चियाममयाणा 7. मेहत 8. कांसर 9. सल्टेवानी 10. बागना कोटड़ी 11. बायला	–यथोपरि–	–यथोपरि–
14.	ग्राम पंचायत, भरोग बनेडी	1. भरोग बनेड़ी 2. पुन्ड़ली 3. बकाहन 4. केलेवाला 5. समौण 6. कनौण 7. खैर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
15.	ग्राम पंचायत, भनेत हल्दवाड़ी	1. कुडला खरक 2. कण्डोला 3. ठाकर कुज्जेवाला 4. भनेत 5. ठाकर गवाणा	–यथोपरि–	–यथोपरि–
16.	ग्राम पंचायत, कोटड़ी ब्यास	1. कोटड़ी 2. चंदपुर 3. ब्यास 4. भुड	–यथोपरि–	–यथोपरि–
17.	ग्राम पंचायत, कुण्ड़ियों	1. कुण्ड़ियों 2. अजीवाला 3. टोका नगला 4. गुलाबगढ़ 5. खारा	–यथोपरि–	–यथोपरि–

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (गृह)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Home-(A)B(1)-29/2016 dated 11th September, 2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. Home-(A)B(1)-29/2016.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal

Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to upgrade the Police Post, Majra to Police Station, Majra and transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station mentioned in Column No. 4 to the local area of the Police Station mentioned in Column No.5 of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2	Police Station from which transferred	Police Station in which included
1	2	3	4	5
1.	Gram Panchayat, Puruwala	1. Santoshgarh 2. Amargarh 3. Puruwala Kanshipur 4. Balluwala	Police Station, Paonta Sahib.	Police Station Majra.
2.	Gram Panchayat, Pipliwala	1. Pipliwala 2. Johron 3. Kiratpur 4. Bhagwanpur	–do–	–do–
3.	Gram Panchayat, Misserwala	1. Misserwala 2. Kyarda	–do–	–do–
4.	Gram Panchayat, Palhori	1. Palhori 2. Simbal Bara	–do–	–do–
5.	Gram Panchayat, Majra	1. Naya Gaon Majra 2. Fatehpur 3. Jagatpur 4. Melion 5. Churak Majri 6. Matak Majri	–do–	–do–
6.	Gram Panchayat, Sainwala Mubarikpur	1. Sainwala 2. Tokiyon 3. Behrewala 4. Khairi 5. Ghunghlon	–do–	–do–
7.	Gram Panchayat, Dhaula Kuan	1. Dhaula Kuan 2. Bharapur	–do–	–do–
8.	Gram Panchayat, Kolar	1. Kolar 2. Sukhchainpur 3. Fandi Bodiwala	–do–	–do–

9.	Gram Panchayat, Haripur Khol	1. Kodewala 2. Charanawala 3. Jheelbanka Bara 4. Lohgarh 5. Jamnighat 6. Mehta Wala	–do–	–do–
10.	Gram Panchayat, Barthal Madhana	1. Saha 2. Madhana 3. Janglot 4. Barthal	–do–	–do–
11.	Gram Panchayat, Rampur Bharapur	1. Ghunghlon 2. Rampur Majri 3. Rampur Banjaran	–do–	–do–
12.	Gram Panchayat, Parduni	1. Parduni 2. Giri Nagar 3. Mehrad	–do–	–do–
13.	Gram Panchayat, Kando Kansar	1. Swara Nadasi 2. Mandhara 3. Kando Fagar 4. Katwadi Bagrat 5. Tanlog 6. Chiyamamyana 7. Mehat 8. Kansar 9. Saltewani 10. Bagna Kotri 11. Bayla	–do–	–do–
14.	Gram Panchayat, Bharog Baneri	1. Bharog Baneri 2. Pundli 3. Bakahan 4. Kelewala 5. Samaun 6. Kanaun 7. Khair	–do–	–do–
15.	Gram Panchayat, Bhanet Haldwadi	1. Kudla Kharak 2. Kandola 3. Thakar Kujjewala 4. Bhanet 5. Thakar Gawana	–do–	–do–
16.	Gram Panchayat, Kotri Bias	1. Kotri 2. Chandpur 3. Bias 4. Bhud	–do–	–do–

17.	Gram Panchayat, Kundiyon	1. Kundiyon 2. Ajiwala 3. Toka Nagla 4. Gulabgarh 5. Khara	–do–	–do–

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 12 सितम्बर, 2017

संख्याः गृह(ए)बी(1)–28 / 2016.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 कीधारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित अनूसूची की स्तम्भ संख्याः 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्याः 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्याः 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र को अन्तरित करते हैं, अर्थात्:–

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायत का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना जिससे अन्तरित किए जाने हैं	पुलिस थाना जिसमें सम्मिलित किए जाने हैं
1	2	3	4	5
1.	ग्राम पंचायत, समोह	1. विजयपुर 2. कजैल 3. रैली 4. निहाण 5. जंगल ढिंगू 6. नेरस 7. समोह	पुलिस थाना सदर बिलासपुर	पुलिस थाना झण्डुता
2.	ग्राम पंचायत, गालियां	1. गालियां 2. तुगंडी 3. सेर 4. जंगल तुगंडी 5. बरोआ	–यथोपरि–	–यथोपरि–
3.	ग्राम पंचायत, डाहड	1. डाहड 2. डफेर	–यथोपरि–	–यथोपरि–

		3. देहलवीं 4. संध टिक्करी 5. डैहण 6. कुठेड़ा		
4.	ग्राम पंचायत, डमली	1. डमली 2. कोहिना 3. घराडसानी 4. छत 5. भटेड़ 6. समलेटा 7. भरोईयां 8. पटट्ा 9. बैहलग 10. चौकी ऋषिकेश 11. कसन्युर दून 12. जंगल गराई	–यथोपरि–	–यथोपरि–
5.	ग्राम पंचायत, बडोल	1. बडोल 2. जमली 3. धन्नतर 4. तन्युर 5. जवाहा 6. पोली 7. थुराहण	–यथोपरि–	–यथोपरि–
6.	ग्राम पंचायत, वैहना जट्टां	1. वैहना जट्टां 2. कोठी 3. लदेहडा 4. सोफता 5. बैरी दड़ौला 6. कल्लर	–यथोपरि–	–यथोपरि–
7.	ग्राम पंचायत, रोहल	1. ज्योरा 2. मुकड़ा ना 3. दोकडू 4. नारल 5. लैहड़ 6. नंड नगराओ 7. रोहल 8. वधोल	–यथोपरि–	–यथोपरि–
8.	ग्राम पंचायत, बलघाड़	1. बलघाड़ 2. पराहूं 3. घराड 4. अमरोआ 5. ठप्पर 6. जंगल रोहाण	–यथोपरि–	–यथोपरि–

		7. जंगल मटेरी 8. जंगल खजुरैहल		
9.	ग्राम पंचायत, बैहना ब्राह्मणा	1. बाला 2. बैहरन 3. बैहना ब्राह्मणा	–यथोपरि–	–यथोपरि–
10.	ग्राम पंचायत, झण्डुता	1. झण्डुता अब्बल 2 झण्डुता दोयम 3 झण्डुता सोयम	–यथोपरि–	–यथोपरि–
11.	ग्राम पंचायत, जांगला	1. जांगला 2. सलासी 3. सुन्दडु 4. मेखवीं 5. जमोई 6. खुडाई 7. खिरसी 8. घन्यार 9. चुआव	–यथोपरि–	–यथोपरि–
12.	ग्राम पंचायत, हीरापुर	1. कसेह 2. हीरापुर 3 वडोआ	–यथोपरि–	–यथोपरि–
13.	ग्राम पंचायत, औहर	1. औहर 2. भजवांणी	–यथोपरि–	–यथोपरि–
14.	ग्राम पंचायत, बैरी मियां	1. जजर 2. कल्याड़ा 3. बैरी 4. बरसंड	–यथोपरि–	–यथोपरि–
15.	ग्राम पंचायत, गेहड़वीं	1. क्यारी 2. छुमाण 3. गेहड़वीं 4. चंगर 5. सेरूवा	–यथोपरि–	–यथोपरि–
16.	ग्राम पंचायत, नखेलेहड़ा	1. खलसाय 2. मुच्छाण 3. मातला 4. नखलेड़ा 5. घराण 6. पसोल 7. टिहरी 8. बसन्द वाड़ी 9. पसोल	–यथोपरि–	–यथोपरि–

17.	ग्राम पंचायत, दाड़ी बाड़ी	1. दाड़ी–बाड़ी 2. रच्छेहडा 3. कारहवीं 4. समलेटू 5. कुलाहर	–यथोपरि–	–यथोपरि–

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव (गृह)।

————————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Home-(A)B(1)-28/2016 dated 12th September, 2017 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th September, 2017

No. Home-(A)B(1)-28/2016.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station mentioned in Column No.4 to the local area of the Police Station mentioned in Column No.5 of the SCHEDULE given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayat	Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2	Police Station from which transferred	Police Station in which included
1	2	3	4	5
1.	Gram Panchayat, Samoh	1. Vijaypur 2. Kajail 3. Railli 4. Nihan 5. Jangal Dhingu 6. Neras 7. Samoh	Police Station Sadar Bilaspur	Police Station Jhandutta
2.	Gram Panchayat, Galian	1. Galian 2. Tungri 3. Ser 4. Jungle Tungri 5. Baroha	–do–	–do–

3.	Gram Panchayat, Dahad	1. Dahad 2. Dafer 3. Dehlwin 4. Sandh Tikkari 5. Dehan 6. Kuthera	–do–	–do–
4.	Gram Panchayat Damli	1. Damli 2. Kohina 3. Ghardsani 4. Chhat 5. Bhater 6. Samleta 7. Bharoyian 8. Patta 9. Behlag 10. Chowki Rishikesh 11. Kasnour Doon 12. Jungle Garari	–do–	–do–
5.	Gram Panchayat, Badol	1. Badol 2. Jamli 3. Dhanatar 4. Tanaur 5. Jawaha 6. Poli 7. Thuran	–do–	–do–
6.	Gram Panchayat, Behna Jattan	1. Behna Jattan 2. Kothi 3. Ladehra 4. Softa 5. Beri- Darolan 6. Kallar	–do–	–do–
7.	Gram Panchayat, Rohal	1. Jayora 2. Mukrana 3. Dokru 4. Naral 5. Lehar 6. Nand-Nagrao 7. Rohal 8. Badhol	–do–	–do–
8.	Gram Panchayat, Balghar	1. Balghar 2. Parahu 3. Gharar 4. Amroa 5. Thapper 6. Jungle Rohan 7. Jungle Materi	–do–	–do–

		8. Jungle Khajuraihal		
9.	Gram Panchayat, Behna Brahmna	1. Bala 2. Behran 3. Behna Brahmna	–do–	–do–
10.	Gram Panchayat, Jhandutta	1. Jhandutta Abbal 2. Jhandutta Doaum 3. Jhandutta Soyam	–do–	–do–
11.	Gram Panchayat, Jangla	1. Jangla 2. Salasi 3. Sundru 4. Mekhwin 5. Jamoi 6. Khudai 7. Khirsi 8. Ghanyar 9. Chuaav	–do–	–do–
12.	Gram Panchayat, Hirapur	1. Kaseh 2. Hirapur 3. Badoha	–do–	–do–
13.	Gram Panchayat, Auhar	1. Auhar 2. Bhanjwani	–do–	–do–
14.	Gram Panchayat, Beri Miyan	1. Jajjar 2. Kalyara 3. Beri 4. Barsand	–do–	–do–
15.	Gram Panchayat, Geherwin	1. Kayari 2. Chuman 3. Geherwin 4. Changer 5. Serurwa	–do–	–do–
16.	Gram Panchayat, Nakhelerha	1. Khalsai 2. Muchwan 3. Matla 4. Nakhlera 5. Gharan 6. Pasol 7. Tihari 8. Basand Bari 9. Pasol	–do–	–do–
17.	Gram Panchayat, Dari-Bari	1. Dari-Bari 2. Rachhera 3. Karhwin	–do–	–do–

		4.Samletu 5. Kulhar		

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 12*th September,* 2017

No. Home-(A)B(1)-3/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Sub-Divisional Police Office at Jaisinghpur, district Kangra with its headquarters at Jaisinghpur alongwith creation of following 6 posts of Police personnel in the pay scale for the post of Dy. S.P ₹ 15600-39100+ ₹ 5400 GP, Head Constable ₹ 10300-34800 + ₹ 3600 GP, Constable (a) ₹ 5910-20200 + ₹ 1900 GP (b) ₹ 10300-34800 + ₹ 3200 GP (after 8 years of regular service) and Steno Typist (a) ₹ 5910-20200 + ₹ 2000 GP (b) ₹ 10300-34800 + ₹ 3200 GP (after 2 years of regular service) :—

Name of Sub-Divisional Police Office	Dy. SP	Head Constable	Constables	Steno Typist	Total
Jaisinghpur, District Kangra.	1	1	3 (including Constable Driver)	1	6

In addition, the services of a Sweeper will be outsourced in above office. The Sub-Divisional Police Officer Jaisinghpur, District Kangra will supervise the work of Police Station Lambagaon and newly upgraded Police Station Thural alongwith the works of Police Posts falling under aforesaid Police Stations, if any. The above approval will be subject to the condition to observe all the codal formalities procedurely in advance in this regard.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Home).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–7 / 2017–लेज.––श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता, मण्ड़ी ने उप–मण्डल़ धर्मपुर, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता को उप–मण्डल़ धर्मपुर, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)7/2017-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-7/2017-Legn.—WHEREAS, Shri Santosh Kumar, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Dharampur of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Santosh Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Dharampur of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–16 / 2007–लेज.––श्री यादवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता, मण्ड़ी ने उप–मण्डल़ गोहर, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री यादवेन्द्र कुमार, अधिवक्ता को उप–मण्ड़ल गोहर, जिला मण्ड़ी की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)16/2007- Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-16/2007-Legn.—WHEREAS, Shri Yadvender Kumar, Advocate, Mandi has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Gohar of District Mandi;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Yadvender Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Gohar of District Mandi, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–7 / 2015–लेज.––कुमारी प्रियंका आर्या, अधिवक्ता, सोलन ने उप–मण्डल़ सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुमारी प्रियंका आर्या, अधिवक्ता, सोलन को उप–मण्ड़ल सोलन, जिला सोलन की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)7/2015-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-7/2015-Legn.—WHEREAS, Ms. Priyanka Arya, Advocate, Solan has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Solan of District Solan;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Ms. Priyanka Arya, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Solan of District Solan, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–5 / 2011–लेज.––श्री विकास कश्यप, अधिवक्ता, ऊना ने उप–मण्डल़ अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विकास कश्यप, अधिवक्ता, ऊना को उप–मण्डल अम्ब, जिला ऊना की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)5/2011-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-5/2011-Legn.—WHEREAS, Shri Vikas Kashyap, Advocate, Una has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Amb of District Una;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Vikas Kashyap, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Amb of District Una, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH)
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0ए ल0आर0–ई(9)–55 / 2005–लेज.––श्री नीरज वासु, अधिवक्ता, बिलासपुर ने उप–मण्ड़ल झुंडता, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री नीरज वासु, अधिवक्ता, बिलासपुर को उप–मण्ड़ल झुंडता, जिला बिलासपुर की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)55/2005-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-55/2005-Legn.—WHEREAS, Shri Neeraj Vasu, Advocate, Bilaspur has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Jhandutta of District Bilaspur;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Neeraj Vasu, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Jhandutta of District Bilaspur, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–40 / 2005–लेज.––श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्डल़ शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री योगेश शर्मा, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्डल़ शिमला (ग्रामीण) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)40/2005-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-40/2005-Legn.—WHEREAS, Shri Yogesh Sharma, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Shimla (Rural) of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Yogesh Sharma, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Shimla (Rural) of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–4 / 2016–लेज.––श्री सुशील कुमार, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्ड़ल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सुशील कुमार, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्ड़ल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2016-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-4/2016-Legn.—WHEREAS, Shri Susheel Kumar, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Susheel Kumar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्याः एल0एल0आर0–ई(9)–4 / 2016–लेज.––श्री ब्रहमा नन्द, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्डल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ब्रहमा नन्द, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्ड़ल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2016-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-4/2016-Legn.—WHEREAS, Shri Brahma Nand, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Brahma Nand, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–4 / 2016–लेज.––श्रीमती सुषमा, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्ड़ल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती सुषमा, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्डल शिमला (शहरी) जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)4/2016-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-4/2016-Legn.—WHEREAS, Smt. Sushma, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Smt. Sushma, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Shimla (Urban) of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–41 / 2005–लेज.––कुमारी रीतु देवी, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्ड़ल ठियोग, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, कुमारी रीतु देवी, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्डल़ ठियोग, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLRE (9)41/2005-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-41/2005-Legn.—WHEREAS, Ms. Reetu Devi, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Theog of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Ms. Reetu Devi, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Theog of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that her name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–38 / 2005–लेज.––श्री मोहिन्द्र पराशर, अधिवक्ता, शिमला ने उप–मण्डल़ रामपुर, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप–नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मोहिन्द्र पराशर, अधिवक्ता, शिमला को उप–मण्ड़ल रामपुर, जिला शिमला की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)38/2005-Legn. Dated 11-09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-38/2005-Legn.—WHEREAS, Shri Mohinder Prashar, Advocate, Shimla has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Rampur of District Shimla;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule (2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Mohinder Prashar, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Rampur of District Shimla, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum-Pr. Secretary (Law).

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2014-Leg-II. Dated 11 - 09-2017 as required under Article 348(3) of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2017

No. LLR-E(9)-6/2014-Leg-II.—WHEREAS Shri Rattan Singh Chauhan, Advocate was appointed as Public Notary *vide* Government Notification No.LLR-E(9)-30/95-Leg. dated 15-09 1998 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmour and his name was entered at serial No.78 in the Register of Notaries;

AND WHEREAS, President Bar Association Paonta Sahib, District Sirmour has intimated vide letter dated 27-06-2017 that Shri Rattan Singh Chauhan, Advocate and Notary Public of Paonta Sahib of District Sirmour has died on 27-05-2017;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Rattan Singh Chauhan, Notary Public of Sub-Division Paonta Sahib of District Sirmour from the Register of Notaries with immediate effect.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
LR-cum- Pr. Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 सितम्बर, 2017

संख्या एल0एल0आर0–ई(9)–6 / 2014–लेज–11.––क्योंकि श्री रतन सिंह चौहान, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना संख्या0 एल0 एल0 आर0–ई(9)–30 / 95–लेज तारीख 15–09–1998 द्वारा उप–मण्ड़ल पावंटा साहिब, जिला सिरमौर के लिए नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 78 पर प्रविष्ट किया गया था;

और क्योंकि प्रधान, बार एसोसिएशन पावंटा साहिब, जिला सिरमौर ने पत्र दिनांक 27–06–2017 द्वारा सूचित किया है कि श्री रतन सिंह चौहान, नोटरी पब्लिक पावंटा साहिब, जिला सिरमौर का देहान्त दिनांक 27–05–2017 को हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रतन सिहं चौहान, नोटरी पब्लिक, उप–मण्डल़ पावंटा साहिब, जिला सिरमौर का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
(डॉ0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 8th *September*, 2017

No. LLR-B(1)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation of following 6 (Six) posts of various categories in the pay scales/ wages shown against each of them in the Himachal Pradesh State Legal Services Authority and Alternative Disputes Resolution Centre(s) Kangra at Dharamshala and Una constituted under the Legal Services

Authorities Act, 1987 in the current Financial Year 2017-2018 subject to the condition that the posts shall be filled up on or before 28-02-2018 after completing all the codal formalities as required therein:—

Posts for H.P. State Legal Services Authority

Sr. No.	Name of Post	Number of Post(s)	Pay Scale	Distribution of Posts
1.	Personal Assistant (Promotional post)	1	Rs.10300-34800+4800 GP	H.P. State Legal Services Authority
2.	Junior Office Assistant (IT) (Contract basis)	1	Rs.5910-20200+1950 GP	----do---
Posts for ADR Centres Kangra at Dharamshala and Una				
3.	Chowkidar-cum-Peon (On Daily Wage basis)	2	Rs. 210/- per day	ADR Centre(s) Kangra at Dharamshala and Una one each.
4.	Sweeper-cum-Peon (On Daily Wage basis)	2	Rs. 210/- per day	----do----

The post of Personal Assistant will be filled up by promotion, the post of Junior Office Assistant (IT)will be filled up by way of direct recruitment on contract basis and two posts of Chowkidar-cum-Peon & two posts of Sweeper-cum-Peon will be filled up on Daily wage basis.

The expenditure will be debited to Major Head 2014-Administration of Justice and Election, 800-Other Expenditure, 02-Himachal Pradesh State Legal Services Authority (Non-Plan) during the current financial year 2017-2018.

This is being issued with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* their Diary No.54083109 Fin (PR) dated 29-08-2017.

By order,
(Dr. BALDEV SINGH),
L.R.-cum-*Pr. Secretary (Law).*

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है